भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 188
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

उद्यम पंजीकरण और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म

188. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री तापिर गाव :
श्री विद्युत बरन महतो :
श्री लुम्बाराम चौधरी :
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्री दामोदर अग्रवाल :
श्री जनार्दन सिह सीग्रीवाल :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित दिसंबर 2025 तक उद्यम पंजीकरण और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्मों पर पंजीकृत उद्यमों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया में जनजातीय और महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनकी बेहतर पहुंच और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए देशभर में और विशेषरूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बजट 2025-26 में घोषित संशोधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) वर्गीकरण मानदण्डों का ब्यौरा क्या है जिसमें निवेश और कारोबार की सीमा में वृद्धि की गई है;

(घ) संशोधित वर्गीकरण के माध्यम से एमएसएमई के दायरे में और अधिक उद्यमों को शामिल करने और उनके लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) भीलवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान में एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) एमएसएमई के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या डिजिटल पहल की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर पंजीकृत उद्यमों का, महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार विवरण, 'अनुबंध-I' पर संलग्न है।

(ख) : महाराष्ट्र और पालघर जिले सहित देश के सभी राज्यों में जनजातीय और महिला उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए बेहतर पहुंच और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में जागरूकता कार्यक्रम, पंजीकरण शिविर, एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से सहायता, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय शामिल हैं। इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) : बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के वर्गीकरण के संशोधित मानदंड की घोषणा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि हुई थी:

वर्गीकरण	निवेश (करोड़ रुपए में)		टर्नओवर (करोड़ रुपए में)	
	पिछला	संशोधित	पिछला	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	1	2.5	5	10
लघु उद्यम	10	25	50	100
मध्यम उद्यम	50	125	250	500

उच्चतर स्तर पर दक्षता प्राप्त करने के लिए, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच के लिए, एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाया गया था। निवेश और टर्नओवर के पुनर्वर्गीकरण के लिए इसकी अधिकतम सीमा में विस्तार करने से विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों के लिए अभिप्रेत लाभों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ङ) : राजस्थान में पंजीकृत एमएसएमई का जिला-वार विवरण, जिसमें भीलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, का विवरण 'अनुबंध-II' में संलग्न है।

(च) : निवेश और टर्नओवर के दोहरे मानदंडों के आधार पर एमएसएमई की संशोधित परिभाषा 2020 में अपनाई गई थी और दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना का.आ. 2119(ई) जारी की गई थी। उद्यमों को सुविधाजनक बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 01.07.2020 को उद्यम के पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया था। उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया स्वैच्छिक है, यह पूरी तरह से ऑनलाइन, मुफ्त, कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए आधार नंबर और पैन पर्याप्त है। ओटीपी के माध्यम से आधार के ऑनलाइन सत्यापन द्वारा उद्यम पंजीकरण का प्रमाणीकरण किया जा रहा है। विनिर्माण या सेवा या दोनों सहित गतिविधियों की किसी संख्या को स्व-घोषणा के आधार पर एक पंजीकरण में निर्दिष्ट या शामिल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है और मंत्रालय की ओर से कोई मानवीय हस्तक्षेप इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा, एमएसएमई का समर्थन करने और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल और ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल जैसी पहल भी की गई हैं।

******

अनुबंध-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 188, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 से 31/12/2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म(यूएपी) पर पंजीकृत एमएसएमई का राज्य-वार विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21,304
2	आंध्र प्रदेश	37,30,420
3	अरुणाचल प्रदेश	45,700
4	असम	14,08,993
5	बिहार	40,26,392
6	चंडीगढ़	76,982
7	छत्तीसगढ़	12,78,375
8	दिल्ली	13,69,330
9	गोवा	1,25,506
10	गुजरात	41,62,294
11	हरियाणा	18,96,164
12	हिमाचल प्रदेश	3,27,300
13	जम्मू और कश्मीर	8,02,511
14	झारखंड	14,77,633
15	कर्नाटक	47,65,355
16	केरल	17,66,147
17	लद्दाख	19,590
18	लक्षद्वीप	2,398
19	मध्य प्रदेश	45,77,924
20	महाराष्ट्र	96,55,164
21	मणिपुर	1,69,355
22	मेघालय	67,974
23	मिजोरम	49,756
24	नागालैंड	71,285
25	ओडिशा	22,91,239
26	पुडुचेरी	1,04,713
27	पंजाब	20,40,646
28	राजस्थान	41,98,176
29	सिक्किम	34,398
30	तमिलनाडु	59,32,903
31	तेलंगाना	36,28,324
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	33,986
33	त्रिपुरा	3,03,585
34	उत्तर प्रदेश	80,43,602
35	उत्तराखंड	6,10,361
36	पश्चिम बंगाल	50,80,154
	कुल:-	**7,41,95,939**

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल

अनुंबध –II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 188, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (ङ) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 से 31/12/2025 तक राजस्थान राज्य में यूआरपी और यूएपी पर पंजीकृत जिला-वार एमएसएमई		
क्र.सं.	**जिला**	**पंजीकृत एमएसएमई**
1	अजमेर	2,23,017
2	अलवर	2,06,025
3	बालोतरा	8,833
4	बांसवाड़ा	70,824
5	बारां	55,378
6	बाड़मेर	94,107
7	ब्यावर	11,833
8	भरतपुर	82,913
9	भीलवाड़ा	1,82,411
10	बीकानेर	1,63,381
11	बूंदी	66,870
12	चित्तौड़गढ़	1,00,585
13	चुरू	1,12,023
14	दौसा	83,497
15	डीग	6,160
16	धौलपुर	34,882
17	डीडवानाकुचामन	16,101
18	डूंगरपुर	57,607
19	गंगानगर	1,36,982
20	हनुमानगढ़	1,06,322
21	जयपुर	7,16,100
22	जैसलमेर	34,573
23	जालौर	56,839
24	झालावाड़	75,738
25	झुंझुनू	1,15,331
26	जोधपुर	2,44,244
27	करौली	42,852
28	खैरथल-तिजारा	7,972
29	कोटा	1,60,391
30	कोटपुतली-बेहरोड़	12,619
31	नागौर	1,62,449
32	पाली	1,16,238
33	फलोदी	6,911
34	प्रतापगढ़	36,813
35	राजसमंद	70,858
36	सलुम्बर	3,627
37	सवाई माधोपुर	55,067
38	सीकर	1,65,953
39	सिरोही	47,828
40	टोंक	78,704
41	उदयपुर	1,67,318
	कुल	41,98,176

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल